सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः
₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

मुख्यमंत्री जितना जल्द हो सका कदम उठाएं उतना...

» Pg 12

कानपुर, शुक्रवार, 20 जून, 2025
वर्षः 02, अंकः 170, पृष्ठः 8+4

इनसाइड 'दबंग बाबू' लंबी छुट्टी पर कार्रवाई की अटकलें... » Pg 02

आजमगढ़ आतंक का नहीं अदम्य साहस का गढ़ : योगी

सलारपुर में आयोजित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर बोले सीएम योगी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आजमगढ़। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने सलारपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। जनसभा स्थल पर नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने लोकार्पण कर जनता को संबोधित किया। कहा कि अब आजमगढ़ आतंक का गढ़ नहीं अदम्य साहस का गढ़ बन गया है।

सीएम योगी ने कहा कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 में लड़ी आजादी की लड़ाई अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होता रोड कनेक्टिविटी तेज होती तो तभी आजमगढ़ के साथ पूरा देश आजाद होता। कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले पूर्वांञ्चल में सिर्फ वोट मांगने आते थे, आज प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ते हुए विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। काशी, विंध्याचल, चित्रकूट, अयोध्या के बाद अब तो हम मथुरा और वृंदावन की तरफ भी भिड़ गए हैं।

उन्होंने कहा कि विरासत के साथ-साथ विकास पर भी काम करेंगे। सीएम ने कहा जो

सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करेगा, पहले से उसका टिकट रिजर्व कर दिया जाएगा। पहले विकास के नाम पर यह लोग डी कंपनी को पालते थे, यानी दाउद कंपनी। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को जहन्नुम का टिकट दे दिया।गौरतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़े गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.35 किमी है। यह गोरखपुर के एनएच-27 पर जैतपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है।चार जिलों गोरखपुर, संतकबीरनगर, आंबेडकरनगर और आजमगढ़ से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेस-वे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण सहित 7283.28 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसका निर्माण दो भाग में गोरखपुर के जैतपुर से अंबेडकरनगर के फुलवरिया तक (48.317 किमी) और फुलवरिया से आजमगढ़ के सलारपुर तक (43.035 किमी) किया गया है।

वापसी यात्रा रद्द

दिल्ली-पुणे एअर इंडिया की फ्लाइट से पक्षी टकराया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुंबई। दिल्ली से पुणे जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में शुक्रवार को पक्षी टकरा गया। इस वजह से एयरलाइन को अपनी वापसी की यात्रा रद्द करनी पड़ी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और पक्षी टकराने का पता पुणे में उतरने के बाद चला। यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था और भोजन उपलब्ध कराने सहित सभी व्यवस्थाएं कर रही है। पैसों की वापसी या यात्रा को फिर से निर्धारित करने वाले विकल्प की पेशकश की जा रही है। साथ ही यात्रियों के लिए दिल्ली जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले एअर इंडिया ने शुक्रवार को विमान की जांच, रखरखाव, खराब मौसम और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों की वजह से कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं। भावित उड़ानों में दुबई, मेलबर्न, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई के बीच की सेवाएं शामिल हैं।

दो बच्चों की हत्या

पूछताछ में मां मुस्कान ने उगल दिया सच

प्रेम-प्रसंग में मां ने जहर देकर मौत की नींद सुलाए मासूम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रुड़कली गांव में दो मासूमों की मौत के मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है। पूछताछ में मां मुस्कान ने खुद ही बच्चों को जहर देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब प्रेम प्रसंग की कड़ी जोड़ने में जुटी है।

मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा के रुड़कली तालाब अली गांव में चार साल के भाई अरहान और एक साल की बहन अनाया की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई। पुलिस पूछताछ में मां मुस्कान की ओर से ही दोनों बच्चों को जहर देने का मामला सामने आया है। पुलिस पूछताछ कर रही है।

थाना क्षेत्र के रुड़कली तालाब अली निवासी वसीम चंडीगढ़ में वेल्डिंग कार्य करता है। वह दो दिन पहले ही अपने गांव से कार्य

पर गया था। उसकी पत्नी मुस्कान बच्चों के साथ घर में मौजूद थी। घर में ही बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी थी। पहले परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने मुस्कान से मोबाइल मांगा, लेकिन वह नहीं दिखा सकी। इसके बाद शक होने पर पूछताछ की, जिसके बाद वारदात का खुलासा हो गया। मुस्कान ने ही दोनों बच्चों को जहर दिया था। पुलिस जांच में जुटी है।

पहले यह बताई थी कहानी : मुस्कान का कहना है कि दोपहर के समय उसके दोनों बच्चे और वह सो गए थे। दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब उसके पति वसीम का फोन आया तो उसकी आंख खुली। उसने देखा तो उसके दोनों बच्चे अचेत मिले। बात उसने अपने पति को बताई तो पति ने अपने भाई डॉ. अकरम को बताया। डॉ अकरम प्रैक्टिस करते हैं। वह वहां से दौड़े और आकर देखा तो दोनों बच्चे मृतक मिले।

मुस्कान का मोबाइल भी हो गया गुम

जैसे ही बच्चों की मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो मामले की जानकारी करने के बाद पुलिस ने वसीम की पत्नी मुस्कान से फोन मांगा, जिस पर मुस्कान ने बताया उसका फोन यहीं पर रखा था पता नहीं कहां गुम हो गया। नंबर लेने के बाद पुलिस ने कॉल करनी चाहिए तो स्विच ऑफमिला। आखिर मोबाइल चोरी हुआ है या छुपाया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

वसीम की मुस्कान से हुई दूसरी शादी

वसीम के परिजनों के अनुसार लगभग सात वर्ष पूर्व वसीम की शादी ककरौली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी युवती के साथ हुई थी। लेकिन लगभग डेढ़ वर्ष के बाद दोनों एक साथ ना रह सके फैसला हो गया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष पूर्व तेवड़ा की ही रहने वाली मुस्कान से शादी हुई।

दबंगई

...... स्वराज इंडिया की खबर का असर......

बिल्हौर तहसील का 'दबंग बाबू' लंबी छुट्टी पर मीडिया में खबर आने के बाद कार्रवाई की अटकलें

» स्वराज इंडिया की पड़ताल में हुआ था खुलासा

» कर्मचारी डर के मारे नहीं खोल पाते अपना मुंह

» क्या नए एसडीएम कर पाएंगे कोई कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील का एक दबंग बाबू मीडिया में खबर आने के बाद लंबी छुट्टी पर चला गया है। इस घटना को लेकर तहसील परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि यह बाबू पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका है, जिसके कारण इसके सामने कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता था। इसी वजह से इसके हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि तहसील के अधिकारी भी इससे कुछ कहने से कतराते थे, जिससे यह लगातार बेलगाम होता गया।

जानकारी के अनुसार, बिल्हौर तहसील में निगम बाबू के पास जन सूचना का पटल है। आरोप है कि यह जन सूचना देने से बचने के लिए जन सूचना के आवेदनों को रिसीव ही नहीं करता है और उन्हें दूसरे-तीसरे पटल पर भेज देता है। जिसके कारण अंत

में वे वापस लौटा दिए जाते हैं। बीते दिनों एक पोस्टमैन ने इसका खुलासा किया था और प्रमाण उपलब्ध कराए थे। स्वराज इंडिया ने इस मामले की पड़ताल करते हुए एक खबर प्रकाशित की थी। इस खबर का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने लिखा-पढ़ी की। इसके बाद हड़कंप मच गया। सूत्रों की मानें तो कार्रवाई से बचने के लिए यह बाबू 15 दिन की मेडिकल लीव पर चला गया है।अब सवाल इस बात का है कि क्या नए एसडीएम इन गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों पर नकेल कसेंगे और लंबे समय से पटरी से उतरी बिल्हौर तहसील की व्यवस्था को फिर से पटरी पर ला पाएंगे?

बिल्हौर तहसील परिसर में गहराया पेयजल संकट, मोटर खराब, लोग बूंद-बूंद पानी को तरसे

» दो सप्ताह बाद भी नहीं किया गया कोई प्रयास

» पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटक रहे लोग

स्वराज इंडिया न्यूज

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील परिसर में पिछले दो सप्ताह से जलापूर्ति ठप पड़ी है, जिससे स्थानीय लोग और तहसील आने वाले फरियादी पीने के पानी के लिए परेशान हैं। तहसील में लगा मुख्य मोटर खराब होने के कारण पानी की टंकी नहीं भर पा रही है। जिसके कारण पूरे तहसील परिसर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। जगह-जगह लगे वाटर कूलर सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी ही नहीं आ रहा है।इस गंभीर पेयजल संकट से तहसील कर्मचारी, वकील, और दूर-दराज से अपनी शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों को जूझना पड़ रहा है। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए या तो बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है या फिर दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है।

दो दिन पहले ही नए एसडीएम ने चार्ज संभाला था। उनके सामने यह समस्या रखी गई थी। जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द इसका समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। जलापूर्ति जैसी समस्या पर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और निष्क्रियता प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।वकीलों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मोटर की मरम्मत कराने और तहसील में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं बार एसोसिएशन बिल्हौर के महामंत्री महेंद्र कुशवाहा ने कहा है बीते कई दिनों से तहसील में पानी की किल्लत है, जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए।

FOLLOW UP

बजट नहीं है तो फिर कैसे सही होगा मोटर!

बिल्हौर। यदि तहसील के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो इस मद में कोई बजट नहीं है। ऐसी स्थिति में मोटर कौन सही कराएगा और किस मद से सही कराएगा। यह यक्ष प्रश्न है। जिसका जवाब समय के गर्त में है। बताया जाता है कि इस मद में जल्दी बजट नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह समस्या और भी गहरा सकती है।

कानपुर और आसपास अभी और भीषण बारिश के आसार

» मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 3 दिन घनघोर बरसेगा मॉनसून

» मानसून की पहली बारिश से कानपुर के कई इलाके जलमग्न

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। **उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की पूरी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश में वर्षा में व्यापक वृद्धि होने की संभावना बन गई है।**

शुक्रवार को प्रयागराज समेत 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें से कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है।

मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून ने 18 जून को सोनभद्र से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था। अब 19 जून तक यह बिहार के अधिकांश हिस्सों को आच्छादित करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। फिलहाल 20 जून को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में अनेक स्थान पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

इस दौरान दोनों हिस्सों में बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है।

पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संतरविदास नगर

और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी है।

वहीं, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर,

उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी है।

सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी निलबित, कहा- न्याय के लिए हाई कोर्ट जाएंगे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने निलंबित होने के बाद डीएम जितेंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ मुंह खोला। यह भी कहा कि वह न्याय के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। सीएसए स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में डीएम पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि डीएम उनसे पैसा मांगते रहे और सिस्टम में आने की सलाह देते रहे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया तो उनका निलंबन कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों को भी उन्होंने स्थिति बताई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ।

डीएम और सीएमओ के बीच तनातनी का माहौल गुरुवार को निष्कर्ष पर पहुंच गया। शासन ने सीएमओ डॉ. नेमी को निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबन के बाद सीएमओ डॉ. नेमी खुलकर डीएम और अपने दूसरे विरोधियों के खिलाफ आ गए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्पीड़न के कारण छह महीने में उनका 10 किलो वजन घटा है। वह डिप्रेशन में चले गए।

इस पर उन्होंने डीएम, एसीएमओ डॉ. सुबोध प्रकाश, डॉ. आरएन सिंह, फाइनेंस अधिकारी वंदना सिंह और जेएम फार्मा को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने उत्पीड़न की सारी बात बताई थी। अब सब कोर्ट में जाकर जवाब दें।

निलंबन को एकतरफा कार्रवाई करार देते हुए उन्होंने कहा कि पहले विभागीय जांच होनी चाहिए। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होती है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। डॉ. नेमी ने बताया कि उन्होंने 16 दिसंबर 2024 को सीएमओ का कार्यभार संभाला था। डीएम ने हर बैठक में उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वह दलित समाज से आते हैं तो दलित सूचक गंदे शब्द कहे। इससे उनका दम घुटता रहा। उनके सिर पर पुश किया जिससे माथा माइक से टकरा गया। उनका आरोप है कि डीएम बराबर पैसे की डिमांड करते रहे। जेएम फार्मा को गलत कार्य विस्तार दिया गया। उस सामान के भुगतान के लिए दबाव बनाया जाता रहा जो सप्लाई ही नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि भुगतान न करने पर जीएम फार्मा, पद से हटाए जाने पर दोनों एसीएमओ डीएम के साथ एक हो गए। डॉ. सुबोध के खिलाफ भाजपा और आरएसएस के लोगों ने भी शिकायत की। उन्होंने पद से हटाए जाने के बाद 30 नर्सिंगहोमों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उनकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है। वह सप्लाई से भी जुड़े रहे। जेएम फार्मा को छुट्टी के दिन 15 दिन का विस्तार दिया। यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में संचारी रोग अभियान में जिला प्रदेश में प्रथम रहा है। वह विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे, उलटे उन्हीं पर कार्रवाई हो गई।

ग्राम राय गोपालपुर में बिना अनुमति मिट्टी खनन का मामला, राजस्व जांच में खुली पोल

आरोपी प्रधान राजेश कुमार

डीपीआरओ मनोज कुमार ने माना घोटाला, उच्चाधिकारियों को सौंपी रिपोर्ट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चौबेपुर ब्लॉक की राय गोपालपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान राजेश कुमार द्वारा नाले की खुदाई के नाम पर की गई अवैध मिट्टी बिक्री का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर होता जा रहा है।

ग्रामीणों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया कि प्रधान ने बिना किसी वैध आदेश या स्वीकृति के गांव की जमीन से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी खुदवाकर बेच दी थी।

यही नहीं, इस कार्यवाही में ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत बने ऋाब्ट सेंटर का प्रवेश द्वार भी जेसीबी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

ग्रामीणों ने मामले की शिकायत ब्लॉक और जिला स्तर तक पहुंचाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके की जांच कराई गई। अब डीपीआरओ की पुष्टि ने इस अवैध खनन की कहानी को नया मोड़ दे दिया है।

डीपीआरओ मनोज कुमार का बयान

ग्राम राय गोपालपुर में ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इस मामले की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। दोषी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।

पीडीए की एकता से बनेगी सपा सरकार: विनय यादव

सुनौडा में चौपाल, अखिलेश को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर(कानपुर)। गुरुवार को चौबेपुर के ग्राम सुनौडा गंभीरपुर गांव में समाजवादी पार्टी की पीडीए चौपाल आयोजित हुई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने कहा कि पाल समाज का असली सम्मान समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। उन्होंने 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट होना होगा।राष्ट्रीय सचिव बैकुंठ नाथ भारतीय ने कहा कि समाजवादी विचारधारा को घर-घर पहुंचाकर संगठन को मज़बूत करेंगे। चौपाल में बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

श्री गौरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED HOSPITAL)
यू.पी.एस.आई.डी.सी. जैनपुर, कानपुर देहात
Mob: 9710106661, 73310106662, 7310106663
अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्कैन, डिजिटल एक्सरे की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध
- आई0सी0यू0/सी0सी0यू0।
- वेंटीलेटर, ए0वी0जी0ए0, कारडियक मॉनीटर, मल्टीपैरा मॉनीटर की सुविधा।
- C-Arm युक्त वतानुकूलित ऑपरेशन थियेटर।
- ट्रामा स्पोर्ट हेड इन्जुरी का सफल इलाज।
- डिजिटल एक्स.रे, सी.टी. स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड (U.S.G.) की सुविधा

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज उपलब्ध है।
टी.पी.ए. कैशलेस की सुविधा उपलब्ध

उपलब्ध सुविधाएं:- ए0बीजी0ए0 मशीन
1. अत्यंत कम वजन के नवजात शिशु एवं समय से पहले जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल। 2. नवजात एवं बाल्य गहन चिकित्सा इकाई ;च्प्ब्न्द्ध 3. चौबीस घंटे मेडिकल स्टोर, एक्सरे, पैथालॉजी, कैन्टीन की सुविधा। 4. नि:शुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। 5. दूरबीन द्वारा पित्त एवं गुर्दे, यूरेटर की पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। 6. गहन चिकित्सा इकाई, वेंटीलेटर सुविधा सहित। 7. सभी प्रकार के हड्डी रोग एवं ट्रामा सम्बंधित ऑपरेशन। 8. सिजेरियन ऑपरेशन/डिलेवरी/बच्चेदानी का ऑपरेशन अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर। 9. कार्डियक मीनीटरिंग/इको कार्डियोग्राफी/सोनोग्राफी/टी.एम.टी.

डा. संजय त्रिपाठी
एम.बी.बी.एस., एमडी मेडिसिन
फेलोशिप क्रिटिकल केयर

विजय बाजपेई
मैनेजिंग डायरेक्टर

सम्पादकीय

पंजाब में दूर होगी डॉक्टरों की कमी

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि पंजाब के सरकारी अस्पताल मरीजों के बढ़ते बोझ से चरमरा रहे हैं। समाज के गरीब व निम्न मध्यमवर्गीय मरीजों के उपचार की अंतिम शरण स्थली ही होते हैं सरकारी अस्पताल। विडंबना यह है कि सरकारी अस्पताल खुद ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों के लिये स्वीकृत पदों में आधे पद फिलहाल खाली है। नई पीढ़ी के डॉक्टर मरीजों के दबाव व आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के चलते सरकारी अस्पतालों को कार्यस्थली बनाने से गुरेज करते रहे हैं। निस्संदेह, निजी क्षेत्र में मोटी तनख्वाह व सुविधाएं उन्हें आकर्षित करती हैं। इधर विदेशों का मोह भी उन्हें खूब लुभाता है। यही वजह है कि ग्रामीण ही नहीं, शहरी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तो ज्यादा ही कमी है। इस समस्या से निबटने के लिये पंजाब सरकार इस सत्र से एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों के लिए बॉन्ड नीति लेकर आई है। निश्चय ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टरों की पुरानी कमी से निपटने के लिये एक ऐसा साहसिक कदम उठाना बेहद जरूरी था। नये नियमों के तहत, राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों से स्नातक करने वाले डॉक्टरों को दो साल के लिये अनिवार्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सेवा करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो बीस लाख रुपये की बॉन्ड राशि का भुगतान करना होगा। वहीं अखिल भारतीय कोटे के तहत स्नातकों को अनिवार्य रूप से एक साल की सेवा सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में देनी होगी। हालांकि, यह नीति बाध्यकारी है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का एक जिम्मेदार प्रयास है कि राज्य चिकित्सा शिक्षा में निवेश का कुछ लाभ राज्य के लोगों को भी मिलना चाहिए। यह तार्किक बात है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को राज्य सरकार भारी सब्सिडी भी देती है।

दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिये करदाताओं द्वारा एक अंशदान दिया जाता है। यह उचित होगा कि छात्र स्नातक होने के बाद समाज में कुछ योगदान जरूर दें। यह इसलिये भी जरूरी है कि राज्य के सरकारों अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बहुत अधिक विकट है क्योंकि आमतौर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से कतराते हैं। बताया जाता है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत डॉक्टरों के 3,847 पदों में पचास फीसदी पद रिक्त हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सकों के न होने का खमियाजा मरीजों को चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के रूप में भुगतना पड़ता है। उन्हें मजबूरी में निजी अस्पतालों के महंगे उपचार लेने के लिये बाध्य होना पड़ता है। वर्षों से यह ट्रेंड चला आ रहा है कि डॉक्टर निजी प्रैक्टिस या विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में सार्वजनिक चिकित्सा सेवा से किनारा करते रहे हैं। निश्चित रूप से बॉन्ड नीति इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्रयास करेगी। इसके साथ ही कतिपय छात्र समूहों का बॉन्ड नीति का विरोध भी समझ में आता है। लेकिन बॉन्ड नीति को खत्म करने की बजाय उनकी चिंता बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनाए जाने के लिये हो। साथ ही कैरियर प्रगति के बेहतर अवसरों के मुद्दों को भी संबोधित किए जाने की जरूरत है। निस्संदेह, एक साल या दो साल का अनिवार्य कार्यकाल एक उचित मांग है, खासकर जब यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती दे सके।

हवा में मौजूद डीएनए में जीवन के सुराग

मुकुल व्यास

नए शोध से पता चलता है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसमें भी उस क्षेत्र में प्रजातियों का नक्शा बनाने, रोगजनकों को ट्रैक करने और मानव गतिविधि से उत्पन्न होने वाले रासायनिक संकेतों का पता लगाने के लिए पर्याप्त डीएनए होता है।यह बात कुछ चौंकाने वाली हो सकती है कि मनुष्य का डीएनए वातावरण में हर जगह मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा (यूएफ) के रिसर्चरों द्वारा किए गए एक अध्ययन में दूरदराज के इलाकों, समुद्रों और नदियों से लेकर हवा तक लगभग हर जगह मानव डीएनए पाया गया है। हम इन सभी जगहों पर खांसते हैं, थूकते हैं या अपने डीएनए को फ्लश करते हैं। रिसर्चरों ने जांच के दौरान लगभग सभी तरह के वातावरण में उच्च क्वालिटी के मानव डीएनए की मौजूदगी देखी। यह आनुवंशिक सामग्री हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है।

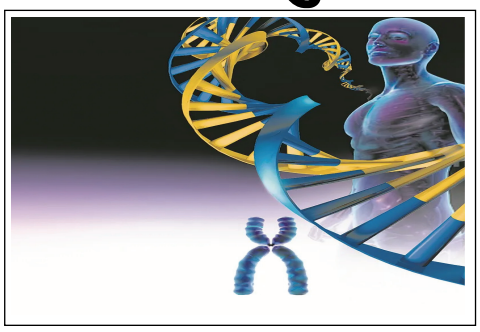

आयरलैंड की राजधानी डबलिन में किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक सामग्री को शहर के वातावरण में बहते हुए पाया। उन्होंने शहर की हवा में ??अवैध नशीली दवाओं के निशान भी खोजे। आसपास के वातावरण में मौजूद आनुवंशिक सामग्री को पर्यावरणीय डीएनए या एनवायरमेंटल डीएनए (ईडीएनए) कहा जाता है। हवा में मौजूद डीएनए में जीवन के सुराग छिपे हैं। नए शोध से पता चलता है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसमें भी उस क्षेत्र में प्रजातियों का नक्शा बनाने, रोगजनकों को ट्रैक करने और मानव गतिविधि से उत्पन्न होने वाले रासायनिक संकेतों का पता लगाने के लिए पर्याप्त डीएनए होता है। इस अध्ययन के प्रोजेक्ट लीडर डेविड डफी की टीम ने यूएफ की विटनी लैबोरेटरी में लुप्तप्राय समुद्री कछुओं और वायरल कैंसर का अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय डीएनए का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। उन्होंने रेत में कछुओं के ट्रैक्स से उपयोगी डीएनए निकाला है। वैज्ञानिकों को पता था कि मानव ईडीएनए उनके कछुओं के नमूनों में मिल सकता है और शायद कई अन्य स्थानों पर भी यह डीएनए मिल सकता है जहां उन्होंने सर्वे किया था। आधुनिक आनुवंशिक सीक्वेंसिंग तकनीक से पर्यावरण के नमूने में प्रत्येक जीव के डीएनए को क्रमबद्ध करना अब आसान हो गया है। रिसर्चरों की टीम को विटनी लैब के आसपास समुद्र और नदियों में, शहर के आसपास और मानव बस्ती से दूर के स्थानों तथा अलग-थलग समुद्र तटों से रेत में अच्छी क्वालिटी वाले मानव डीएनए मिले।

अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस की मदद से किए गए एक परीक्षण में रिसर्चरों ने एक दूरस्थ द्वीप के उस हिस्से की यात्रा की जहां लोग कभी नहीं गए थे। यह स्थान मानव डीएनए से मुक्त था। लेकिन वे इस क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रतिभागियों के पैरों के निशान से डीएनए निकालने में सफल रहे। उन्होंने प्रतिभागियों की अनुमति से उनके जीनोम अथवा डीएनए समूह के कुछ हिस्सों को क्रमबद्ध भी किया। वैज्ञानिकों ने एक पशु चिकित्सालय से कमरे की हवा के नमूने भी एकत्र किए। इन नमूनों की मदद से वे कर्मचारियों, एक पशु रोगी और सामान्य पशु विषाणुओं से मेल खाने वाले डीएनए को अलग करने में सफल रहे। डफी ने कहा कि पर्यावरणीय डीएनए में उपलब्ध जानकारी के स्तर को देखते हुए हमने इस बात पर विचार शुरू कर दिया है कि मनुष्यों, वन्यजीवों और अन्य प्रजातियों में इसके संभावित अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की विटनी लैब ने हवा सहित लगभग हर वातावरण से डीएनए निकालने और उसका विश्लेषण करने के अपने तरीकों को व्यापक बनाया है। यह डीएनए सिर्फ सतह पर नहीं रहता। यह हवा में भी स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है।शोधकर्ताओं ने पाया कि घंटों या कई दिनों तक चलने वाले साधारण एयर फिल्टर बड़ी मात्रा में सूचनात्मक आनुवंशिक सामग्री एकत्र कर सकते हैं। डफी ने कहा, जब हमने शुरुआत की, तो ऐसा लगा कि हवा से डीएनए के बड़े टुकड़े प्राप्त करना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम वास्तव में बहुत सारे सूचनात्मक डीएनए प्राप्त रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्रजातियों को सीधे परेशान किए बगैर उनका अध्ययन कर सकते हैं।

संतुष्ट जीवन के लिए योग के संयोग

योग दिवस

सुचिता खन्ना

यदि हम किसी नवयुवक से आग्रहपूर्वक योग को अपनाने के लिए कहें तो वह हमसे पूछ सकता है, 'मेरे लिए योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है?' निश्चित रूप से उसके प्रश्न का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देने के लिए स्वयं हमें इसका उत्तर ज्ञात होना चाहिए। निस्संदेह, पिछले एक दशक से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत ने हमारे जीवन में योग के शाश्वत महत्व को उत्सव के रूप में मनाने में सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व किया है।

फिर भी, जैसा कि हममें से कुछ लोग जानते हैं कि योग का सही अर्थ इसकी आंतरिक एवं गहन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में निहित है। योग और ध्यान की वैज्ञानिक पद्धतियों का नियमित अभ्यास हमें उस ईश्वर के साथ एकता की दिव्य खोज की ओर ले जाता है, जिस पर संसार के सभी धर्म बल देते हैं; यह खोज कालांतर में प्रेरित होती है और अंततः संभव भी होती है। क्रियायोग आध्यात्मिक अभ्यास की पद्धति सच्चे योगी को अन्ततः जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिए गए उपदेश में दो बार क्रियायोग का उल्लेख किया है। दरअसल, अनेक सदियों की

मानवीय अज्ञानता के पश्चात उन्नीसवीं शताब्दी में महान आध्यात्मिक गुरु लाहिड़ी महाशय ने अपने शाश्वत गुरु महावतार बाबाजी के आशीर्वाद से इस महत्वपूर्ण और शुद्ध विज्ञान की पुनः खोज की। तत्पश्चात लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी श्रीयुक्तेश्वर गिरिजी ने कालांतर में अपने शिष्य श्री श्री परमहंस योगानन्द को क्रियायोग का गहन ज्ञान प्रदान किया।कालांतर में योगानन्द जी ने मानव कल्याण के लिये क्रियायोग के वैश्विक दूत होने का संकल्प किया और इसके लाभों का सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में प्राणपण से प्रचार किया। आज सम्पूर्ण विश्व में उनके लाखों अनुयायी योग-ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियों का अभ्यास निरंतर करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से क्रियायोग मार्ग का ही विस्तार है। योगानन्दजी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध और तमाम वैश्विक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक 'योगी कथामृत' में अत्यंत प्रेरक ढंग से इसका वर्णन किया है, 'माया या प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्यों में प्राणशक्ति का प्रवाह हमेशा बाह्य जगत की ओर होता है और इन्द्रियों में प्राणशक्ति का व्यय हो जाता है। साथ ही गाहे-बगाहे उसका दुरुपयोग भी होता है। सुखद ही है कि क्रियायोग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है; प्राणशक्ति को मन द्वारा अन्तर्जगत में ले जाया जाता है, जहां प्राणशक्ति मेरुदण्ड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राणशक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नवशक्ति प्राप्त होती है।'

निश्चित रूप से क्रिया योग हमारे तन-मन के साथ ही आध्यात्मिक कल्याण करता है। योगी कथामृत पुस्तक से हम यह भी सीखते हैं।

सपना चौधरी का है 'बालम छोटा'

नया गाना हुआ रिलीज, हरियाणवी डांसर ने डाला देसी तड़का

मुंबई। टी सीरीज हरियाणवी के धमाकेदार नए गाने बालम छोटा में सपना चौधरी ने डांस का जलवा बिखेर दिया। टी सीरीज हरियाणवी नया गाना बालम छोटा लेकर आया है। यह एक जोशीला, रंगीन डांस नंबर है, जो हरियाणा की धड़कन को सीधे आपके स्क्रीन तक पहुंचाता है।

सपना चौधरी की दमदार मौजूदगी के साथ ये गाना भरपूर तड़क, स्टाइल और डांस फ्लोर एनर्जी से भरा है। गाने को अपनी दमदार आवाज़ दी है रुचिका जांगिड़ ने, और इसके बोल लिखे हैं मोहित मज़ारिया ने। सीआर म्यूजिक का कम्पोज़िशन इस गाने को एक जबरदस्त फेस्टिव वाइब देता है। साहिल संधू के निर्देशन में बना म्यूज़िक वीडियो उतना ही रंगीन और एनर्जेटिक है जितना गाना खुद है। द आर्ट गैंग रा बनाए गए विजुअल्स और वेस्टर्न बीट्स की प्रोडक्शन ने इस प्रोजेक्ट को एक यादगार अनुभव बना दिया है। गाने के बारे में सपना चौधरी ने कहा, बालम छोटा ऐसा ट्रैक है जो आपको बिना सोचे नचाने पर मजबूर कर देता है। इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में हैं लेकिन इसका जोश और मस्ती एकदम रिफ्रेशिंग है। इसकी शूटिंग करना मेरे लिए एक टोटल फन एक्सपीरियंस था। ये गाना पूरी तरह से जश्न है।

ठग लाइफ पर प्रतिबंध से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाईं फटकार, बैन को बताया गलत

मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ठग लाइफ को आवश्यक कानूनी प्रावधानों को पालन किये बगैर कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को अगले 24 घंटे के अंदर जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली महेश रेड्डी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

प्रतिबंध के लिए मजबूर नहीं कर सकती राज्य सरकार

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह दलील दिए जाने के बाद कि इस विवाद के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, पीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि वह उसे (याचिका) शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश देगी।

अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि एक बार जब फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो भीड़ थिएटर मालिकों को डरा धमकाकर उसके प्रदर्शित करने पर पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर नहीं कर सकती।

रेड्डी की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस

इससे पहले 13 जून को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस (शीर्ष अदालत की) पीठ ने इस फिल्म पर प्रतिबंध के खिलाफ रेड्डी की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के पालन किए बगैर (न्यायेतर प्रतिबंध) राज्य में ठग लाइफ फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया दिया।

रेड्डी की याचिका पूरी तरह से गलत

इस बीच, इस मामले (सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका) में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए कन्नड़ साहित्य परिषद ने शीर्ष अदालत के समक्ष आवेदन किया है। हस्तक्षेप आवेदन में आरोप लगाया गया है कि फिल्म पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता रेड्डी का इस विषय से कोई लेना-देना नहीं है।

मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ठग लाइफ को आवश्यक कानूनी प्रावधानों को पालन किये बगैर कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को अगले 24 घंटे के अंदर जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली महेश रेड्डी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

आरआरसी सेंटरों की दुर्दशा पर सीडीओ ने मानी चूक, जांच और सुधार का ऐलान

- स्वराज इंडिया की रिपोर्ट पर प्रशासन ने लगाई मुहर, सीडीओ ने मानी आरआरसी सेंटरों की बदहाली
- 30.5 करोड़ की योजना पर सवाल बरकरार, जांच और जवाबदेही की घड़ी शुरू

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। स्वराज इंडिया की पड़ताल में सामने आई आरआरसी सेंटरों की बदहाली अब प्रशासनिक पुष्टि पा चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीक्षा जैन ने खुद स्वीकार किया है कि जिले की 305 ग्राम पंचायतों में बनाए गए इन सेंटर्स की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सत्य है। बंद पड़े, बिना उपयोग के वीरान ढांचे अब सिर्फ सरकारी खर्च के प्रतीक बनकर रह गए हैं।

सीडीओ ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉकवार जांच करवाई जाएगी ताकि जमीनी वास्तविकता की और गहराई से पुष्टि हो सके। साथ ही, जिन स्थानों पर निर्माण में खामियां या लापरवाही पाई जाएगी, वहां मरम्मत के साथ-साथ जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही भी की जाएगी।

भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगीं, प्रशासन अब लेगा हिसाब

भारी भरकम बजट के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। दीवारों का दरकना, ताले लगे रहना, और सेंटरों का अनुपयोगी होना सीधे तौर पर निर्माण एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करता है। अब जब प्रशासन ने स्वयं इस चूक को मान लिया है, तो सवाल यह उठता है कि ?30.5 करोड़ की इस योजना में किस स्तर पर निगरानी की कमी रही। क्या अब तक कोई ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है? और क्या ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई समयबद्ध होगी या यह जांच भी सिर्फ कागज़ों में सिमट जाएगी?

सीडीओ कानपुर दीक्षा जैन का आधिकारिक बयान

स्वराज इंडिया की रिपोर्ट में जिन आरआरसी सेंटरों की स्थिति दिखाई गई है, वह सही पाई गई है। हमने ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में जांच के निर्देश दे दिए हैं। जो सेंटर अनुपयोगी हैं या निर्माण में गड़बड़ी है, उन्हें ठीक कराया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि यह योजना अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर लौटे और जनता को इसका लाभ मिल सके। **मुख्य विकास अधिकारी(सीडीओ) कानपुर दिक्षा जैन**

जीवन ज्योति बनी उम्मीद की किरण, मौत के बाद भी दिया आर्थिक सहारा

» शाखा प्रबंधक ने दी पासबुक, योजना से जुड़ने की अपील

» ग्रामीण बैंक की पहल से तीन मृतक आश्रितों को मिले दो-दो लाख रुपये

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अब ज़रूरतमंद और बेसहारा परिवारों के लिए संजीवनी बन रही है। रसूलाबाद क्षेत्र के तिश्ती गांव स्थित ग्रामीण बैंक में बुधवार को तीन मृतक खाताधारकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

शाखा प्रबंधक मनु मुदगल ने बताया कि जिन खातों से नियमित रूप से जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि जमा होती है, उनके निधन के उपरांत नामित आश्रितों को ?2 लाख की राशि दी जाती है। इसी क्रम में मृतक गुड्डी देवी के पति रामनरेश (निवासी मनावा), चंद्रपाल की पत्नी राममूर्ति (निवासी धर्मुपुर) और उर्मिला के पति नरेश चंद्र के खातों में यह राशि ट्रांसफर की गई।

शाखा प्रबंधक ने मृतकों के परिजनों को प्रिंटेड पासबुक सौंपी और योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण बैंक की यह योजना असमय मौत के बाद परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत देती है।

उन्होंने सभी खाताधारकों से अपील की कि वे इस योजना से जुड़ें ताकि भविष्य में किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को सहारा मिल सके। साथ ही, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी समय से लेने की सलाह दी।

दबंग प्रधान पर जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी का आरोप

पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर को दी तहरीर, प्रधान पर गाली-गलौज और हत्या की धमकी देने का भी आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पुखरायां कस्बे के रहने वाले एक युवक ने भोगनीपुर के ग्राम प्रधान अब्दुल अनीस मलिक पर जबरन उसकी खेती की जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

शास्त्री नगर निवासी रहमतुल्ला टाइगर का कहना है कि उसका खेत गाटा संख्या 437, भोगनीपुर गांव में स्थित है। आरोप है कि ग्राम प्रधान अब्दुल अनीस ने दबंगई दिखाते हुए जबरन खेत की मेड़ तोड़ दी और जमीन को अपने खेत में मिला लिया।

पीड़ित के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया तो प्रधान ने गाली-गलौज की और धमकी दी कि 卐हमारे लोग हैं, तुझे जान से मरवा देंगे।卐 रहमतुल्ला ने बताया कि गुरुवार को जब वह पुखरायां में था, तभी उसने प्रधान से जमीन छोड़ने को कहा, जिस पर उसे खुलेआम धमकाया गया।

रहमतुल्ला ने इस मामले में उप-जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर को लिखित शिकायत देकर कब्जा हटवाने और सुरक्षा की मांग की है।

क्षेत्राधिकारी संजय सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

भोगनीपुर हाईवे पर बना जल जमाव जाल, पलट रहे वाहन, घायल हो रहे यात्री

» ओवरब्रिज के नीचे भरा दो फीट पानी, गड्ढों में गिर रहे रिक्शा और बाइक सवार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज के नीचे बारिश के बाद जमा हुए दो फीट पानी ने यात्रियों की राह मुश्किल कर दी है। गुरुवार रात से हुई हल्की बारिश के चलते सर्विस रोड पर जलभराव हो गया है, जिससे खासकर दोपहिया वाहन व बैटरी रिक्शा चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के नीचे छिपे गड्ढों के कारण वाहन पलट रहे हैं और चालक व सवार घायल हो रहे हैं।स्थानीय नागरिकों ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशक झांसी से तत्काल जल निकासी की मांग की है। परियोजना निदेशक ने आश्वासन दिया है कि संबंधित कर्मचारियों को भेजकर जल निकासी का कार्य कराया जाएगा। बताते चलें कि यह मार्ग कानपुर, झांसी, इटावा और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जिस पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। बावजूद इसके, बारिश में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यह मार्ग खतरे का केंद्र बन गया है।

राशनकार्ड सत्यापन को मिला एक माह का अल्टीमेटम, अपात्रों की होगी छुट्टी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्डों का सत्यापन कार्य एक माह में शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। शासन की मंशा के तहत यह अभियान जाली, मृतक या आर्थिक रूप से अपात्र व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने की शिकायतों को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। जिले में प्रचलित 51,147 अन्त्योदय कार्डों की गहन जांच की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि कहीं मृतक के नाम पर राशन तो नहीं उठाया जा रहा, या अपात्र परिवार इस योजना का अनुचित लाभ तो नहीं ले रहे। विशेषकर विधवा, विकलांग, निराश्रित बुजुर्गों तथा आदिवासी परिवारों को वरीयता देने के निर्देश भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

» मृतकों के नाम पर जारी कार्ड, अपात्रों की सूची में दर्ज लोग बनेंगे कार्रवाई के केंद्र

»नए पात्रों का चयन ग्राम सभा की बैठक में, फर्जीवाड़े पर तय होगी जिमेदारी

पात्र गृहस्थी कार्डों की जांच तहसील और नगरीय निकायों के नोडल अधिकारियों की देखरेख में की जाएगी। गांव व वार्ड स्तर पर सूची तैयार कर पात्रों को जोड़ा जाएगा और अपात्रों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे। जांच के दौरान आय, भूमि स्वामित्व और सामाजिक स्थिति की पुष्टि क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों से कराई जाएगी। सत्यापन के बाद ग्राम सभा की खुली बैठक में सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए। साथ ही यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि मृतक या अपात्र कोई भी व्यक्ति नई सूची में शामिल नहीं है। यदि सत्यापन के बाद भी अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख का अश्लील बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल

» ब्लॉक प्रमुख आशीष मिश्रा ने दर्ज कराई एफआईआर, कहा कि एआई से ऑडियो बनाकर किया जा रहा बदनाम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अकबरपुर के ब्लाक प्रमुख आशीष मिश्रा का एक आडियो वायरल हुआ है जिसमें इश्क में डूबा प्रेमी अपनी माशूका के साथ रात में नीली फिल्मों सरीखे बातें की जा रही हैं। यकीन करें तो ये संवाद मोहब्बत की चाशनी में डूबे भाजपा के एक माननीय और उसकी माशूका के बीच का बताया जा रहा है। आडियो वायरल करने वाले ने दावा किया यह बातचीत अकबरपुर ब्लाक प्रमुख की है। इस हरकत के खिलाफ ब्लाक प्रमुख ने अज्ञात पर रूरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आडियो की सच्चाई और फरेब को लेकर चर्चाएं तमाम हैं। सच्चाई क्या है कि ये पुलिस ही तय करेगी। हालांकि मामले में रूरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

आशीष मिश्रा बीजेपी ब्लॉक प्रमुख

वायरल आडियो में नेता के तमाम संवाद ऐसे हैं जो कि एक जिम्मेदार अखबार होने के नाते दैनिक भास्कर लिख नहीं सकता। चुनिंदा संवादों की बानगी बयां करती है कि संवाद में अश्लीलता की सारी हदों को लांघ दिया है। वायरल आडियो में कपड़ों के रंग से शुरुआत होती है। फिर अगले शब्द ऐसे शुरु हो जाते हैं जिन्हें लिखने की बात छोड़ो सुनकर ही शर्म आ जाए।

हालाकि इस बातचीत में महिला ने भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वह संवाद में बराबर की भूमिका निभा रही है। फिलहाल ये आडियो जिले में चर्चा का विषय बना है।इस आडियो से ब्लाक प्रमुख आशीष मिश्रा चरित्र को लेकर बातें उछलीं हैं। उन्होंने रूरा थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज करा दी है। दरअसल आशीष रूरा के रहने वाले हैं। वह अकबरपुर से भाजपा ब्लाक प्रमुख हैं। आशीष का कहना है कि उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा। सच्चाई सामने लाने के लिए रिपोर्ट लिखा दी है। अब पुलिस का काम है छानबीन करके सच उजागर करे। उन्होंने कहा कि एआई का दुरुपयोग करके आडियो वायरल किया गया है। इसमें उनकी आवाज नहीं है। वहीं प्रभारी निरीक्षण रूरा जर्नादन सिंह ने कहा कि ब्लाक प्रमुख की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन की जा रही है। मामले आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दिनदहाड़े लूटकांड के तीन लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में दो के पैर में लगी गोली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शुक्लागंज में पुलिस ने मुठभेड़ में तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से कब्जे से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा व दो खोखा कारतूस , व एक काला बैग (लूट का माल) बरामद किया गया।

कानपुर के शुक्लागंज में कोतवाली गंगा घाट के पश्चिमी चौकी क्षेत्र के मोहल्ला गोपीनाथपुरम में दो दिन पहले दिनदहाड़े घर में घुसकर लुटेरों ने महिलाओं संग लूटपाट की थी।

इस मामले में शुक्रवार सुबह पुलिस ने आजाद मार्ग के कटहा गांव मोड़ के पास हुई मुठभेड़ में तीन लुटेरों को पकड़ा है। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने लूट का माल बरामद कर लिया है और लुटेरों के पास से तमंचे व कारतूस भी मिले हैं। बता दें कि 18 जून को गोपीनाथपुरम मोहल्ले में रहने वाली कुसुम श्रीवास्तव के घर में लूट की घटना हुई थी।

इसके बाद एस पी उन्नाव दीपक भूकर ने खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई थी। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पहले ही पकड़ लिया था।

उससे पूछताछ की गई, जिसकी सूचना पर शुक्रवार सुबह आजाद मार्ग के कटहा गांव मोड़ के पास लूट के माल का बंटवारा करते समय लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे मुखबिर ने बताया कि घटना से संबंधित तीनों अभियुक्त पुनः किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं।

तीनों बदमाश थाना गंगाघाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम कटाह होटल गंगा गैलेक्सी के सामने मरहला आजाद मार्ग पर बैठे हैं। सूचना के आधार पर थाना गंगाघाट पुलिस और स्वॉट/सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। तभी दो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

मुठभेड़ में दो बदमाशों दीपक (26) पुत्र स्व. नरेश निवासी जनपद रायबरेली व देवेंद्र सिंह (19) पुत्र सरवन सिंह निवासी जनपद हरदोई के पैर में गोली लगी है। उनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय उन्नाव भेजा गया है। वहीं, तीसरे अभियुक्त आशीष गुप्ता (22) पुत्र कालीचरन निवासी जनपद लखनऊ को दौड़ाकर पकड़ लिया गया।

महमूदाबाद- कुर्सी सड़क चौड़ीकरण में नदी में लगाया बांध

बांध के कारण नदी का पानी आसपास के खेतों में घुस गया, खेत बर्बाद

स्वराज इंडिया संवाददाता

निंदूरा बाराबंकी। लखनऊ- महमूदाबाद- कुर्सी सड़क चौड़ीकरण के दौरान कस्बे में नया पुल बनाए के लिए ठेकेदारों ने नदी में बांध बना दिया। इस बांध के कारण नदी का पानी आसपास के खेतों में घुस गया है।जिससे कई हेक्टेयर फसलें डूब गईं। राष्ट्रीय राज्य मार्ग के तहत सड़क के निर्माण के दौरान गांव बड्डूपुर के पास कल्याणी नदी में बांध बनाया गया है। जिसके कारण 150 बीघा से अधिक फसलें जलमग्न हो जाएगी।

राष्ट्रीय राज्य मार्ग योजना के तहत लखनऊ–महमूदाबाद– कुर्सी पर सड़क के निर्माण के दौरान गांव बड्डूपुर में कल्याणी नदी के पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके चलते कार्यदायी संस्था द्वारा नदी में बांध लगा दिया गया। इस नदी का पानी खेतों में घुस कर मेंथा व धान की नर्सरी की नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि संस्था ने इस पुल का निर्माण कार्य धीमा होने की वजह से गन्दा पानी का जलभराव हो रहा है। किसान इसे लेकर कई दिन पहले शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति जैसी की तैसी है। अगर बरसात होने से पहले बाँध न हटाया गया तो किसानो की फसल का काफी नुकसान होगा। नदी के पुल को कार्यदायी संस्था ने आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। इस कारण अब कल्याणी नदी का पानी खेतों में घुस रहा है।

बाराबंकी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल

तबादला एक्सप्रेस में कई थाना प्रभारियों पर गाज गिरी, और उन्हें पुलिस लाइंस का रास्ता दिखाया गया है

- पुलिस लाइंस भेजे गए थाना प्रभारी:
- हैदरगढ़ के प्रभारी निरीक्षक रहे अजय प्रकाश त्रिपाठी
- लोनी कटरा थानाध्यक्ष उप निरीक्षक दोमित्र सेन रावत
- हैदरगढ़ कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह।

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने जनहित और प्रशासकीय समायोजन के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। गुरुवार देर रात चली इस तबादला एक्सप्रेस में कई थाना प्रभारियों पर गाज गिरी, और उन्हें पुलिस लाइंस का रास्ता दिखाया गया है। वहीं, पुलिस लाइंस में प्रतीक्षा कर रहे निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए थानों और चौकियों का प्रभार दिया गया है।

इन थाना प्रभारियो को मिली नई जिम्मेदारिया

सफदरगंज थाना प्रभारी रहे निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह को शिकायत प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है।

सतरिख थाने में लंबे समय से जमे अमर कुमार चौरसिया को हटाकर सफदरगंज थाने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे धीरेन्द्र कुमार सिंह को सतरिख थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।

जहाँगीराबाद थाने के प्रभारी रहे अभय कुमार मौर्य को लोनी कटरा थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।

शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे संजीत कुमार सोनकर को फतेहपुर कोतवाली की कमान सौंपी गई है।

न्यायालय सुरक्षा प्रभारी रहे अभिमन्यु मल्ल को हैदरगढ़ कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है।

अपराध शाखा में तैनात रहे उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद शुक्ला को जहाँगीराबाद थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

न्यायालय सुरक्षा में फेरबदल:

पुलिस लाइंस में रहे निरीक्षक अमित प्रताप सिंह को न्यायालय सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है।

पुलिस लाइंस में ही रहे उप निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी को भी न्यायालय सुरक्षा में तैनात किया गया है।

इन चौकी इंचार्जों के कार्यक्षेत्र में बदलाव:

तबादलों के क्रम में कई चौकी इंचार्जों के भी कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया गया है

फतेहपुर कोतवाली की कस्बा चौकी इंचार्ज रहे संजय कुमार गुप्ता को सफदरगंज थाने की सैदनपुर चौकी का इंचार्ज बनाया गया है।

दरियाबाद थाने की कस्बा चौकी प्रभारी रहे उप निरीक्षक हरि प्रसाद उपाध्याय को फतेहपुर कस्बा चौकी का इंचार्ज बनाया गया है।

उप निरीक्षक बृजभान सिंह चंदेल को घुंघटेर थाने की सैंदर चौकी से चौकी प्रभारी हथौंदा, कोतवाली रामसनेही घाट।

उप निरीक्षक बिशुन कुमार शर्मा को राम सनेही घाट की हथौंदा चौकी से घुंघटेर थाने की पैंदर चौकी।

उप निरीक्षक कालिका प्रसाद को बड्डूपुर थाने की भगौली चौकी से प्रभारी लॉकअप न्यायालय/अभियोजन कार्यालय।

उप निरीक्षक विनय कुमार को मसौली थाने की त्रिलोकपुर चौकी से बड्डूपुर थाने की भगौली चौकी।

उप निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता को पुलिस लाइंस से मसौली थाने की त्रिलोकपुर चौकी।

उप निरीक्षक गौरव अवस्थी को एसएसआई रामसनेही घाट से कस्बा चौकी दरियाबाद।

उप निरीक्षक राजकुमार पटेल को पुलिस लाइंस से एसएसआई रामसनेही घाट।

महिला उप निरीक्षक चंदा यादव को मंडी चौकी नगर कोतवाली से थाना देवा।

उप निरीक्षक रणजीत सिंह को पुलिस लाइंस से नगर कोतवाली।

उप निरीक्षक शशांक पांडेय को नगर कोतवाली से मंडी चौकी भेजा गया है।

न्याय के नाम पर धब्बा बनी अयोध्या की ब्यूरोक्रेसी, आयोग ने खोला मोर्चा

» मंदबुद्धि की जमीन निगल गया सिस्टम,आयोग ने जड़ा तमाचा

» डीएम अयोध्या और एसएसपी को एससी/एसटी आयोग ने भेजा नोटिस

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। बीकापुर के मंदबुद्धि राजितराम की बहन जितना जब थाने से लेकर तहसील और कमिश्नरी तक न्याय की भीख मांगती रही, तब सिस्टम ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अधिकारियों की नींद तोड़ दी है–डीएम अयोध्या और एसएसपी अयोध्या को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है।

जिन अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वे पीड़ित को न्याय दिलाएं, उन्हीं की निष्क्रियता के चलते अब नौ लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है—इनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमरनाथ सोनकर, उपनिबंधक बीकापुर, दस्तावेज़ लेखक और बाकी बिचौलिए शामिल हैं। मामला सिर्फ ज़मीन हड़पने का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता और जातीय उत्पीड़न की चुप सहमति का दस्तावेज़ बन गया है।

पीड़ित राजितराम अपनी बहन जितना के साथ

जितना का आरोप है कि उसका भाई राजितराम बचपन से मंदबुद्धि है, और उसकी अनमोल ज़मीन को तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय की मिलीभगत से हड़प लिया गया। ना उसे गाटा संख्या पता, ना रकबा की समझ। फिर भी उसके नाम बैनामा कैसे हुआ? सवाल सीधा है और जवाब देने से अफसर कतरा रहे हैं।

सवालों के कटघरे में प्रशासन

क्या ज़मीन हड़पने वाले और अधिकारी मिले हुए थे?

मंदबुद्धि को बैनामे में कैसे बनाया गया पक्षकार?

आयोग को रिपोर्ट देने से पहले ही क्या दर्ज होगी एफआईआर?

बीकापुर एसडीएम विकास धर दुबे के निर्देश पर आरोपी अनिल कुमार सहित दो लोगो को कोतवाली बुलाकर पूछताछ शुरू की गयी है। एसडीएम के समक्ष पीड़ित राजितराम अपनी बहन जितना और अधिवक्ता प्रदीप पांडेय के साथ पेश होकर पैरवी की थी।

थाना, सीओ, एसपी—सभी दरवाज़े खटखटाए गए, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो जितना ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। अब आयोग ने सीधा प्रशासन को लपेटे में ले लिया है। 15 दिन का अल्टीमेटम जारी है—या तो कार्रवाई करो या भुगतो!

मेरठ में हार्ट अटैक से युवा पार्षद की मौत

» सीने में दर्द होने पर खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंचे युवा पार्षद, 10 मिनट बाद ही हार्ट अटैक से मौत

» अचानक हुई मौत ने झकझोरा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, जीवन की निस्सारता का गहरा बोध कर गई यह विदाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ। मेरठ नगर निगम वार्ड-67 कैलाशपुरी शास्त्रीनगर के पार्षद गगनदीप गौतम (42) का अचानक यूं चले जाना पूरे शहर को स्तब्ध कर गया। एक तेज़तर्रार, मिलनसार नेता जो अपने बूते चुनाव जीतकर भाजपा प्रत्याशी को हराने के बाद स्वयं भाजपा में शामिल हुआ था – वही गगनदीप बृहस्पतिवार सुबह खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल गया, और दस मिनट बाद ही जीवन से हार गया।सुबह अचानक सीने में तेज़ दर्द उठा। पहले भी तीन दिन से हल्का

दर्द था, लेकिन उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवा लेकर बात को टाल दिया था। इस बार दर्द बढ़ा तो दोस्तों को बुलाया, लेकिन उन्हें तकलीफ दिए बिना, स्कूटी खुद चलाकर गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल पहुंच गए।

ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से 200 से ऊपर निकला। ईसीजी में हार्ट की गंभीर समस्या आई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। दोस्त उन्हें दूसरे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली।

उनकी मौत की खबर आग की तरह फैली। पांच साल की बेटी युविका और तीन साल का बेटा धनुष बेसुध हैं। पत्नी रीनू की चीखें हर दिल को चीर रही थीं। परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला रो रहा था।

गगनदीप की कहानी एक चेतावनी बन गई है — कि कैसे आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम शरीर के संकेतों को अनदेखा कर जाते हैं।

इस हृदय विदारक घटना के बाद भाजपा नेता, सांसद अरुण गोविल, राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक समेत कई पार्षद और कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे सूरजकुंड श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। हर चेहरा नम था, हर आंख बोल रही थी — इतनी जल्दी क्यों चले गए?

नगर निगम में भी शोकसभा हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

1 जुलाई से पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य

» निर्णय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के तरफ से ही लिया गया

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। भारत में करोड़ों लोग पैन कार्ड के लिए पूर्ण रूप से आवेदन करते हैं। और फिर सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य भी कर दिया है।और फिर इससे पहले, केवल दस्तावेज अपलोड करने से काम चल जाता था। और ये निर्णय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के तरफ से ही लिया गया है।इससे टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद भी मिलेगी। साथ ही एक ही व्यक्ति द्वारा कई पैन कार्ड बनवाने, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और नकली बिलिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए यह कदम भी उठाया गया है।और मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा निर्धारित भी की गई है।साथ ही समय सीमा पार करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा। और फिर लगभग 13 करोड़ लोग अभी भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करा पाए हैं।

ईरान के क्लस्टर बमों से इजरायल में अफरातफरी

क्लस्टर बम दुनिया के सबसे घातक और विवादास्पद हथियारों में से एक हैं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» ईरान द्वारा इजरायल पर इसके उपयोग ने इस मिसाइल के प्रति लोगों का वैश्विक ध्यान केन्द्रित कर दिया है

» इसके वारहेड्स हवा में नीचे गिरते समय छोटे-छोटे बमों में बंट जाते हैं, जो बड़े क्षेत्र में तबाही मचाते हैं

नई दिल्ली। ईरान-इजरायल युद्ध के सातवें दिन ईरान द्वारा इजरायल पर दागे गये क्लस्टर मिसाइल बम अत्याधिक घातक साबित हुए। ईरान के इस हमले ने इजरायल के नागरिकों का मनोबल बुरी तरह से तोड़ दिया है।क्लस्टर बम जिन्हें गुच्छ युद्ध सामग्री भी कहा जाता है, क्लस्टर बम दुनिया के सबसे घातक और विवादास्पद हथियारों में से एक हैं। ये बम अपनी व्यापक विनाशकारी क्षमता और दीर्घकालिक प्रभावों के कारण युद्ध क्षेत्र में तबाही मचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। युद्ध के दौरान ईरान द्वारा इजरायल पर इसके उपयोग ने इस मिसाइल के प्रति लोगों का वैश्विक ध्यान केन्द्रित कर दिया है।

क्लस्टर बम एक प्रकार का विस्फोटक हथियार है जो हवा में या जमीन से छोड़ा जाता है। यह एक बड़े खोल (कैनिस्टर) के रूप में होता है, जिसमें सैकड़ों छोटे-छोटे विस्फोटक उपकरण, जिन्हें सबम्युनिशन या बॉमलेट्स कहते हैं, भरे होते हैं। ये बॉमलेट्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टैंक-रोधी, कर्मी-विरोधी, या आग लगाने वाले। इनका मुख्य उद्देश्य एक बड़े क्षेत्र में फैलकर अधिकतम नुकसान पहुंचाना है। एक क्लस्टर बम का प्रभाव क्षेत्र कई क्रिकेट मैदानों जितना बड़ा हो सकता है, जिससे यह सैन्य टुकड़ियों, वाहनों, या अन्य लक्ष्यों को व्यापक स्तर पर नष्ट कर सकता है।

किन देशों के पास हैं क्लस्टर बम: क्लस्टर बमों के भंडार और उनके उपयोग को लेकर सटीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि कई देश अपनी सैन्य क्षमताओं को गोपनीय रखते हैं। फिर भी, कुछ देशों के पास इन हथियारों के होने की जानकारी उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लस्टर बमों का बड़े पैमाने पर उपयोग और उत्पादन किया है। रूस के पास भी क्लस्टर बमों का बड़ा भंडार है। यूक्रेन युद्ध में रूस पर इन बमों के उपयोग का आरोप लगा है।

क्लस्टर बम कैसे काम करता है?

क्लस्टर बम की कार्यप्रणाली इसे अन्य पारंपरिक बमों से अलग करती है। इसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, या मिसाइलों के जरिए लक्ष्य क्षेत्र में छोड़ा जाता है। जब यह अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचता है, तो इसका खोल हवा में खुल जाता है, जिससे अंदर मौजूद सैकड़ों बॉमलेट्स बिखर जाते हैं। ये बॉमलेट्स एक बड़े क्षेत्र में फैलकर विस्फोट करते हैं, जिससे व्यापक विनाश होता है। हाल ही में इजरायल-ईरान युद्ध में ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों छोड़े जाने के दौरान देखा गया कि इसके वारहेड्स नीचे गिरते समय छोटे-छोटे बमों में बंट जाते हैं, जो बड़े क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। प्रत्येक बॉमलेट स्वतंत्र रूप से विस्फोट करता है और अपने आसपास के लक्ष्यों को नष्ट करता है। कुछ बॉमलेट्स तुरंत विस्फोट नहीं करते, बल्कि बारूदी सुरंग की तरह जमीन पर पड़े रहते हैं, जो बाद में नागरिकों के लिए खतरा बन जाते हैं।

क्लस्टर बमों की सबसे बड़ी खासियत उनकी व्यापक कवरेज है। ये एक साथ सैन्य और असैन्य लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं, जिसके कारण ये अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। हालांकि, यही खासियत इन बमों को विवादास्पद भी बनाती है। 2008 में क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन के तहत 100 से अधिक देशों ने इनके उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सहमति दी थी।

रूस ने भी सीसीएम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए

हाल के इजरायल-ईरान युद्ध में, ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों के उपयोग की खबरें सामने आई हैं। ईरान ने भी सीसीएम पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इजरायल के पास क्लस्टर बम होने की संभावना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चीन और भारत ने भी सीसीएम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है और संभवतः उनके पास क्लस्टर बमों का भंडार है, हालांकि सटीक संख्या अज्ञात है। कई अन्य देशों, जैसे पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, और सऊदी अरब, के पास भी क्लस्टर बम हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाले विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गौरतलब हो, क्लस्टर बमों का उपयोग मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण से अत्यंत विवादास्पद है। इनके अंधाधुंध प्रभाव के कारण असैन्य नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, को भारी नुकसान होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी, गैर-विस्फोटित बॉमलेट्स बारूदी सुरंगों की तरह काम करते हैं, जिससे दीर्घकालिक खतरा बना रहता है। मानवाधिकार संगठनों, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ने इनके उपयोग की कड़ी निंदा की है। 100 से अधिक देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्रमुख सैन्य शक्तियाँ, जैसे अमेरिका, रूस, और ईरान, इसका उपयोग और भंडारण जारी रखे हुए हैं।

संभल हिंसा : सीडीआर से मिले सबूत

सांसद बर्क के कहने पर सर्वे रोकने को रिजवान ने जुटाई थी भीड़

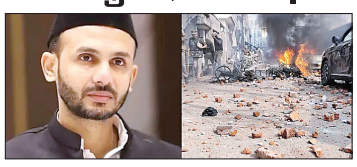

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

संभल। सांसद के व्यक्तिगत सहायक अब्दुल रहमान के पिता रिजवान की भूमिका भीड़ को एकत्र करने में सामने आई है। सांसद के कहने पर रिजवान ने ही फोन कर जामा मस्जिद के आसपास इलाके के साथ सरायतरीन से भीड़ को सवेज़ रोकने के लिए बुलाया था। पुलिस ने चाजज़्शीट में लिखा है कि रिजवान जामा मस्जिद में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम भी करता है। जामा मस्जिद सवेज़ के दौरान हुए बवाल का मुख्य साजिशकताज़ तो पुलिस ने सांसद

मुख्यमंत्री जितना जल्द सख्त कदम उठाएं उतना...

मायावती का योगी को दिया सुझाव, तबादलों में भ्रष्टाचार व हिस्सेदारी की आम चर्चा व खबरें चिंताजनक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादलों का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस विवाद पर अब बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तबादलों में कथित वसूली और पक्षपात को लेकर सरकार को घेरा था। अब मायावती ने इस मामले को लेकर सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकलापों और विभागीय तबादलों में भ्रष्टाचार व हिस्सेदारी की आम चर्चा व खबरें चिंताजनक हैं। मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसका कड़ा संज्ञान

लेकर न केवल विजिलेंस विभाग को सक्रिय करना चाहिए बल्कि एक समयबद्ध एसआईटी का गठन कर जांच करवाना जनहित में आवश्यक है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकारी भ्रष्टाचार व अफसरों की द्वेषपूर्ण मनमानी पर मुख्यमंत्री जितना जल्द सख्त कदम उठाएंगे, उतना प्रदेश और जनता के लिए बेहतर होगा।

सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, विपक्ष आक्रामक : बताते चले कि सीएम योगी ने तबादलों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से आदेशों को निरस्त कर जांच बैठा दी है। मुख्यमंत्री ने साफकर दिया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए।

इस मामले पर स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने खुद इस बात को स्वीकारा कि तबादलों में तमाम खामियां थीं। उन्होंने कहा कि इंटर पास बाबू को रजिस्ट्रार बना दिया गया है और जिनके खिलाफ शिकायत थी, उन्हें बड़े जिलों में पोस्टिंग दे दी गई है।

विपक्षी दलों का सरकार पर दोतरफावार : वहीं सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस मामले पर निशाना साध चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा, वही राज खोलकर सुना रहा है किस्सा। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब मायावती का जुड़ना इस बात का संकेत है कि यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं, बड़े राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो चुका है।

सत्तापक्ष जहां इसे कार्रवाई और पारदर्शिता की मिसाल बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सरकारी भ्रष्टाचार और अंदरूनी खींचतान का नतीजा करार दे रहा है।